सत्यमेव जयते

भूपेन्द्र यादव
Bhupender Yadav
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री
Minister of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार / Government of India

प्राक्कथन

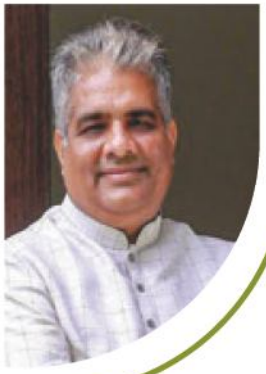

भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता और इसके विकास का वनों से गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव है। सदा से ही वनों का महत्व मानव जाति के विकास और संसाधन आधार के लिए अमूल्य रहा है। आज के समय में, वनों के महत्व को सभी वर्गों ने समझा, और एक वैश्विक समझ भी धीरे–धीरे उभर रही है कि जीवन के लिए मानव जाति को वनों और वृक्ष संसाधनों का सतत् उपयोग सुनिश्चित करना होगा।

राष्ट्रीय वन नीति और अन्य कानून वन संरक्षण के साथ–साथ नागरिकों की आजीविका और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मार्ग निर्धारित करते हैं। आर्थिक मोर्चे पर तीव्र प्रगति के कारण विकास कार्यों और दीर्घकालिक वन संरक्षण में वैज्ञानिक संतुलन की आवश्यकता है। इसलिए नीतिगत दृष्टिकोण से देश में वन और वृक्षों के आवरण की स्थिति का नियमित रूप से अनुश्रवण करना अनिवार्य है।

भारत विश्व के उन गिने–चुने देशों में से एक है जिसके पास समय–समय पर वनावरण और वृक्षावरण के आकलन की एक मजबूत और वैज्ञानिक प्रणाली है। वनावरण और वृक्षावरण का आकलन दो वर्षों के चक्र पर किया जाता है और उसके परिणाम भारतीय वन सर्वेक्षण की द्वि–वार्षिक "भारत वन स्थिति रिपोर्ट" में प्रकाशित होते हैं। इस तरह की प्रथम रिपोर्ट वर्ष 1987 में लायी गई थी तथा तब से 16 "भारत वन स्थिति रिपोर्ट" प्रकाशित की जा चुकी हैं। द्वि–वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्र में वनों की स्थिति की एक विस्तृत और आधिकारिक समीक्षा प्रस्तुत करती है। भारतीय वन सर्वेक्षण की गतिविधियों में विगत कुछ वर्षों में विस्तार हुआ है। डिसीज़न सपोर्ट सिस्टम, वन अग्नि मॉनिट्रिंग प्रणाली, ई–ग्रीन वॉच, उच्च रेजोल्यूशन मानचित्रण और वन इंवेंट्री का आधुनिकीकरण ऐसे अतिरिक्त क्षेत्र हैं जहाँ उल्लेखनीय प्रगति की गई है।

भारत सकारात्मक, रचनात्मक और दूरंदेशी तरीके से UNFCCC के अंतर्गत बहुपक्षीय वार्ता में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य UNFCCC के तहत जलवायु, न्याय और समानता के सिद्धांतों और सामान्य लेकिन अलग–अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के आधार पर एक प्रभावी, सहकारी और न्यायसंगत वैश्विक वास्तुकला स्थापित करना है।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कोविड–19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत की सत्तरहवीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट –2021 तैयार करने का कार्य निर्धारित समय पर पूरा कर लिया गया है। मैं, इस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ को तैयार करने के लिए संस्थान के महानिदेशक, और उनकी टीम को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह रिपोर्ट नीति निर्धारकों, योजनाकारों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, जो राष्ट्र के विशाल वन संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं।

भूपेन्द्र यादव

अश्विनी कुमार चौबे
Ashwini Kumar Choubey
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
Minister of State for Environment,
Forest and Climate Change
भारत सरकार / Government of India

सत्यमेव जयते

प्राक्कथन

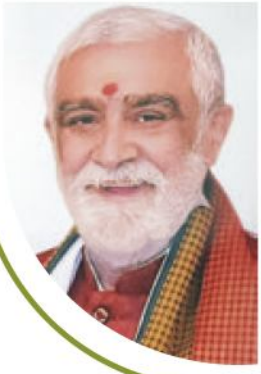

भारतवर्ष की पावन भूमि में मानव और प्रकृति के मध्य, समरसता, सहभाव का एक दीर्घकालीन इतिहास रहा है। भारतीय दर्शन के अनुसार, वनस्पति और जीव एक ही परिवार के सदस्य माने जाते रहे हैं। पारंपरिक रीति–रिवाजों और कला के रूपों की एक विस्तृत कड़ी रही है जो वास्तविक संसाधनों जैसे वन और वृक्ष के सतत् उपयोग का वर्णन करती है। राष्ट्रीय वन नीति के पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जैव–विविधता, जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन / पृथ्क्करण का मूल्यांकन करना आवश्यक है।

भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत, राष्ट्र का एक प्रमुख संस्थान है, जिसे देश के वन संसाधनों के मूल्यांकन का दायित्व सौंपा गया है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रदत्त आंकड़े और मानचित्र राष्ट्र के वानिकी क्षेत्र के नीति–निर्धारण में महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

प्रस्तुत परिणाम, वन संसाधनों के राज्य और राष्ट्रीय, दोनों स्तरों का आकलन दर्शाते हैं। यह जानकारी राज्यों के वन एवं वृक्ष संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन की नीति और रणनीति तैयार करने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि भा०व०स० ने देश के बायोमास मानचित्रण, वनाग्नि अनुश्रवण कार्यक्रमों के लिए एस ए आर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी, इन्वेंट्री आंकड़ों के संग्रहण एवं प्रक्रमण के लिए वास्तविक समय आधारित तथा संबद्ध तकनीकों के लिए विशेष एप्लीकेशन पीडीए उपकरण के उपयोग को अपनाया है। वर्तमान रिपोर्ट में वर्द्धमान निधि आकलन, कार्बन लेखाकरण एवं अन्य मापदण्डों के लिए नए राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री अभिकल्प आंकड़ों का प्रयोग किया गया जिससे अधिक परिष्कृत परिणाम प्राप्त हुए।

मैं, भारतीय वन सर्वेक्षण की पूरी टीम को महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध करवाने के लिए उनके समर्पित प्रयासों हेतु बधाई देता हूँ, जोकि प्रयोक्ता एजेंसियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन की योजना में सहायक सिद्ध होगी।

अश्विनी कुमार चौबे

लीना नन्दन
Leena Nandan
सचिव
Secretary
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार / Government of India

प्राक्कथन

भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आई.एस.एफ.आर) 2021 को जारी करने की घोषणा करना वास्तव में हर्ष का विषय है। यह रिपोर्ट देश में वनों की स्थिति की प्रामाणिक जानकारी प्रदान करती है और इसलिए अनुसंधानकर्ताओं, नीति निर्माताओं, नियोजकों, राज्य वन विभागों और अन्य संस्थानों द्वारा इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण, आई.एस.एफ.आर की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करता आ रहा है और वर्तमान रिपोर्ट, परिशुद्ध आंकड़ों की बृहद मात्रा प्रस्तुत करने के लिए स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ है जो विश्लेषकों के लिए विशिष्ट अवसर प्रदान करती है।

वन हमारी पारिस्थितिकी तंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। देश के वनों पर निरंतर रूप से बढ़ रहे दबावों को देखते हुए, हो रहे परिवर्तनों का पता लगाने और उनकी निगरानी करने की तत्काल आवश्यकता है। हमारे वानिकी मानदंडों जैसेकि वन और वृक्ष आवरण के विस्तार, इमारती लकड़ी की किस्मों के वितरण परिमाण, बायोमास, कार्बन स्टॉक, पुनरुद्भव स्थिति आदि का आवधिक रूप से आकलन करना, वन और भूमि संसाधनों के प्रबंधन में कार्यनीतिक आयोजना सुनिश्चित करने हेतु न केवल वन प्रबंधकों के लिए बल्कि नियोजकों और नीति निर्माताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारतीय वन सर्वेक्षण, 35 से अधिक वर्षों से देश के वन संसाधन का द्विवार्षिक रूप से आकलन करके प्रशंसनीय कार्य करता आ रहा है। वर्तमान रिपोर्ट में केवल वन आवरण, वन सूची और गत आकलन के संबंध में हुए परिवर्तनों से संबंधित सूचना ही नहीं है बल्कि सिंथेटिक अपर्चर रडार (एस.ए.आर) का प्रयोग करके भूमि पर बायोमास (ए.जी.बी) का अनुमान और देश के वन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के हॉटस्पॉट भी समाविष्ट हैं।

मुझे यह जानकर खुशी है कि वर्तमान आई.एस.एफ.आर में अभिलिखित वन क्षेत्रों के अंतर्गत वन आवरण के विस्तार का आकलन करने के लिए 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की डिजिटल वन सीमाओं का उपयोग किया गया है। मैं शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वन विभागों से आग्रह करती हूं कि इस कार्यकलाप को प्राथमिकता के आधार पर आरंभ करें और एफ.एस.आई को सटीक डिजिटल वन सीमाओं का ब्यौरा उपलब्ध कराएं। इससे राज्यों को अभिलिखित वन क्षेत्रों के भीतर और बाहर के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रीति से योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

गत वर्षों में एफएसआई की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों में परिवर्तन हुआ है। आज एफ.एस.आई अनेक जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यकलापों जैसेकि वन संदर्भ स्तर तैयार करना, यूएनएफसीसीसी को जीएचजी की संसूचना, द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर) और संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) रिपोर्ट तैयार करने आदि में संलग्न है। एफ.एस.आई, वैश्विक वन संसाधन आकलन (जीएफआरए) के लिए एफएओ को देश के आंकड़े संसूचित करने के लिए एक नोडल अभिकरण के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा, एफएसआई द्वारा ई–ग्रीन वॉच पोर्टल के अंतर्गत कैम्पा के कार्यकलापों की निगरानी, वन संरक्षण संबंधी मामलों पर त्वरित ढंग से निर्णय लेने के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) के विकास, पूर्वाग्नि चेतावनी संदेश जारी करने आदि जैसी अनेक पहलें भी आरंभ की जा रही हैं।

मुझे विश्वास है कि भारतीय वन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकीय विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा और एक सुदृढ़ राष्ट्रीय वन निगरानी प्रणाली विकसित करने में विशेष योगदान देगा। मैं एफएसआई की टीम को उनके भावी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देती हूँ।

लीना नन्दन

चन्द्र प्रकाश गोयल
Chandra Prakash Goyal
वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव
Director General of Forest & Special Secretary
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार / Government of India

सत्यमेव जयते

प्राक्कथन

मुझे यह जानकर असीम हर्ष हुआ है कि भारतीय वन सर्वेक्षण भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 प्रकाशित कर रहा है। यह संस्थान विगत 35 वर्षों से भारत के वन एवं वृक्षावरण के विस्तार तथा गुणवत्ता पर आंकड़ों की विशालतम संपदा का उत्पादन करने में भूमिधर की तरह सेवा कर रहा है। कार्य–पद्धतियों में तकनीकी उन्नति एवं परिमार्जन के साथ कदम मिलाकर चलना भारतीय वन सर्वेक्षण की एक सतत् प्रक्रिया रही है।

भारत में वनों को अत्यधिक जैविक दबाव का सामना करना पड़ता है। अतः इस प्रकार के दबावों के प्रभाव का जमीन पर लगातार आकलन करना और इस संबंध में राज्य वन विभागों तथा संबंधित एजेंसियों को सतर्क करना आवश्यक है।

भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना से ही वन इन्वेंट्री का कार्य इस संस्थान के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। राष्ट्रीय स्तर पर वनों एवं बाह्य वन वृक्षों की वर्द्धमान निधि को आकलित करने हेतु वर्ष 2002 में राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री की शुरूआत की गई थी। वर्ष 2016 में पूरे राष्ट्र को 5 कि.मी.X 5 कि.मी. की ग्रिड में विभक्त करके ग्रिड आधारित डिज़ाइन वन इन्वेंट्री एवं बाह्य वन वृक्ष दोनों के लिए अपनाया गया। नए डिज़ाइन से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर वन संसाधन आंकलन का समय 20 वर्ष से कम होकर 5 वर्ष हो गया है और साथ ही वन इन्वेंट्री के आंकड़े बेहतर शुद्धता से प्रस्तुत किए जायेंगे।

भारतीय वन सर्वेक्षण जलवायु परिवर्तन (आई.पी.सी.सी.) पर अंतर–शासकीय पैनल द्वारा विकसित गुड प्रैक्टिस गाइडेंस (जी.पी.जी.) की कार्य–पद्धति के अनुसार भारत के वनों में कार्बन स्टॉक का आकलन कर रहा है। विभिन्न संस्तर के लिए उत्सर्जन फैक्टर के आकलन हेतु राष्ट्रीय वन इंवेंट्री (एन.एफ.आई.) के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा विशेष अध्ययन संचालन के माध्यम से बायोमास समीकरण गुणक को विकसित किया गया है। आंकड़ों के संश्लेषण तथा विभिन्न कार्बन निकायों में कार्बन स्टॉक आकलन के लिए जी.आई.एस. तकनीक का प्रयोग किया गया है।

अखिल भारतीय स्तर पर एस.ए.आर. तकनीक का प्रयोग करके बायोमास आकलन के परिणाम को प्रस्तुत किया जा रहा है। पहली बार राष्ट्र के बायोमास मानचित्र को तैयार किया गया है। वन क्षेत्रों के लिए जलवायु परिवर्तन हॉट–स्पॉट अध्ययन का परिणाम भी प्रस्तुत किया जा रहा है। ये जानकारियाँ राज्य वन विभागों एवं अन्य एजेंसियों के लिए उनके प्रबंधन के अधीन वन क्षेत्रों के शमन को डिजाइन करने तथा रणनीति व कार्यक्रमों को अपनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सुसंगत सिद्ध होने के साथ ही राज्य सरकारों के लिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित जरुरतों में उत्पादन द्वारा उनकी भूमि तथा विकास नीतियों के साथ तालमेल करनें में आधार–रेखा का कार्य करेगा।

भारतीय वन सर्वेक्षण की पूरी टीम एक बार फिर से उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हमारी बधाई एवं सराहना की पात्र है।

संस्थान की संपूर्ण टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

चन्द्र प्रकाश गोयल

अनूप सिंह
Anoop Singh
महानिदेशक
Director General
भारतीय वन सर्वेक्षण
Forest Survey of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
भारत सरकार / Government of India

प्रस्तावना

दशकूपसमा वापी, दशवापीसमो ह्रदः।
दशह्रदसमो पुत्रो, दशपुत्रसमो द्रुमः ।।

'Dasha-kupa sama vapi, dasha-vapi sama hradah I
Dasha-hradah samah putro, dasha-putra sama drumah' II

मत्स्य पुराण 154:512

प्राचीन भारतीय ग्रंथ मत्स्य पुराण में कहा गया है कि "एक तालाब दस कुओं के समान होता है, पानी का एक जलाशय दस तालाबों के समान होता है, जल के दस भंडार एक पुत्र के समान होते हैं और दस पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है।"

भारत में प्राचीन काल से ही वृक्षों और वनों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज पूरा विश्व न केवल एक संसाधन के आधार के रूप में, अपितु पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व की कुंजी के रूप में भी वृक्षों और वनों के महत्व की सराहना करने लगा है। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने 2021 के लिए अपने प्रसंग को "वन पुनरूद्धारः समुत्थान व कल्याण का मार्ग" घोषित किया है। इस संदर्भ में भारतीय वन सर्वेक्षण (भा.व.स.) की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य भारत के वन संसाधनों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करना है।

भा.व.स. उपग्रह आंकड़ों का उपयोग करते हुए देश का वनावरण मानचित्रण करता है, जिसके परिणाम एक द्विवार्षिक प्रकाशन में प्रकाशित होते हैं जिसे भारत वन स्थिति रिपोर्ट (भा.व.स्थि.रि.) के तौर पर जाना जाता है। मुझे भारत वन स्थिति रिपोर्ट (भा.व.स्थि.रि.) 2021 को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के उपग्रहों की आई.आर.एस. रिसोर्ससेट श्रृंखला के स्वदेशी लिस –III सैंसर से मध्यम रिजॉल्यूशन उपग्रह आंकड़ों (23.5 मी.) का उपयोग करते हुए 2019–20 अवधि के लिए वनावरण मानचित्रण और वृक्षावरण के आकलन के राष्ट्रव्यापी परिणाम सम्मिलित हैं।

भा.व.स. द्वारा 2016 से अपनाए गए ग्रिड आधारित डिजाइन के बाद भा.व.स्थि.रि. 2021 राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री का आकलन प्रदान करता है। राज्य और जिला स्तर के वनावरण आकलन प्रदान करने के अतिरिक्त, रिपोर्ट में अभिलेखित वन क्षेत्रों (आर.एफ.ए) के भीतर एवं बाहर वनावरण, जनजातीय जिलों, पर्वतीय जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों में वनावरण परिवर्तन विश्लेषण और टाइगर रिजर्व में वनावरण के आकलन पर भी जानकारी प्रदान की गई है।

एक अन्य मुख्य केंद्र नासा के एक्वा और टैरा उपग्रह पर MODIS सेंसर और SNPP-VIIRS सेंसर द्वारा वनाग्नि अनुवीक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। भा.व.स्थि.रि. 2021 ने देश के ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री के उपक्रम में पर्यावरण. वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को मूल्यवान जानकारी प्रदान करने और उन सम्मेलनों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के वनों में कार्बन स्टॉक के आकलन को विशेष महत्व दिया है, जिसमें देश एक हस्ताक्षरकर्ता है।

भा.व.स्थि.रि. 2021 देश के वन क्षेत्रों में जलवायु हॉटस्पॉट क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए बिट्स पिलानी (गोवा कैंपस) के सहयोग से भा.व.स. द्वारा किए गए अध्ययन के परिणाम भी प्रस्तुत करता है। अभियोजित प्रतिकूल जलवायु प्रभावों के कारण जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट क्षेत्रों के विषय में बढ़ी समझ भारतीय वनों

में जलवायु परिवर्तन के विरूद्ध रोकथाम और अनुकूल उपायों की योजना व रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।

भा.व.स्थि.रि. 2021 ने कच्छ वनस्पति और बांस के वनों के गहन विश्लेषण सहित बाह्य वन एवं वृक्षों के आकलन के लिए नवीनतम तकनीक और कार्यप्रणाली के उपयोग से वर्तमान वन आकलन आंकड़ा कोश में मूल्यवान परिवर्धन किया है।

भा.व.स. ने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (एस.ए.सी), इसरो अहमदाबाद के सहयोग से सिंथेटिक अपर्चर राडार (एस.ए.आर) आंकड़ों का उपयोग करके अखिल भारतीय स्तर पर भूमि से उपर बायोमॉस (ए.जी.बी) के आकलन के लिए विशेष अध्ययन किया गया। पूरे देश के ए.जी.बी. आकलन और ए.जी.बी. मानचित्र के अंतरिम परिणाम इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए हैं।

वर्तमान पोर्टल की सीमाओं को दूर करने के लिए भा.व.स. द्वारा ई–ग्रीन वॉच पोर्टल में सुधार भी किया जा रहा है। यह कैंपा बजट के माध्यम से किए गए प्रतिपूरक वनरोपण जैसी विभिन्न गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए समवर्ती निगरानी के साथ–साथ सूचना प्रणाली सुनिश्चित करेगा।

भा.व.स्थि.रि. 2021 के विमोचन के अवसर पर मैं, श्री भूपेन्द्र यादव, माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्री अश्विनी कुमार चौबे, माननीय राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, पूर्व सचिव, एवं श्रीमती लीना नन्दन, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, श्री सुभाष चन्द्र, पूर्व वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं श्री चन्द्र प्रकाश गोयल, वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और डॉ० सुनीश बक्शी, वन महानिरीक्षक (एस.यू.) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का उनके निरंतर समर्थन और अमूल्य मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं भारतीय वन सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशकों डॉ० सुभाष आशुतोष और श्री पंकज अग्रवाल का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने पूरे कार्य का अनुवीक्षण करने और दिशा देने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। मैं संस्थान के अधिकारियों व तकनीकी स्टाफ का कोविड 19 महामारी की चुनौतियों के वनस्पत रिपोर्ट को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने में उनके संपूर्ण समर्पण एवं सहयोग की सराहना करता हूँ।

मैं अद्यतन कार्यप्रणाली तथा तकनीक के प्रयोग से देश के वन संसाधनों पर प्रासंगिक और नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को दोहराता हूँ और संस्थान को दिए गए जनादेश के लिए स्वयं को और अपनी टीम को पुनः समर्पित करता हूँ।

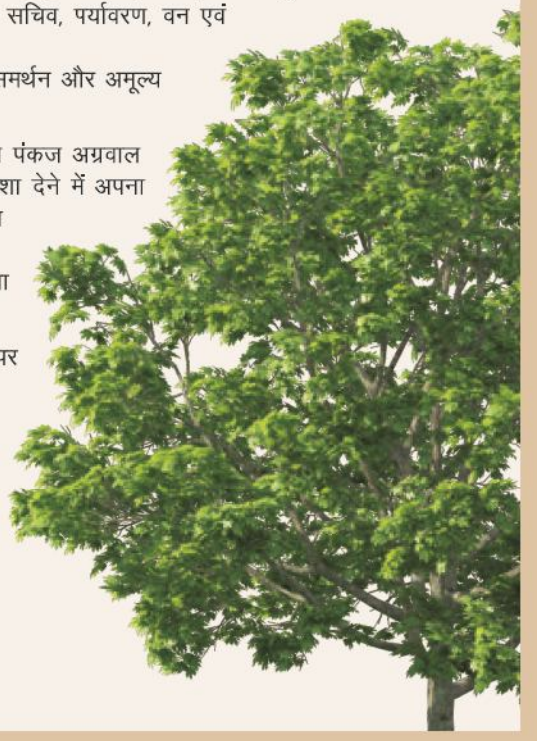

अनूप सिंह